



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542]
No. 542]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 1989/भाद्र 9, 1911
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 1989/BHADRA 9, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

अम मंत्रालय

अम जीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें)
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 के अधीन समाचारपत्र स्थापन
नियोजकों और उनके अम जीवी पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मचारियों
को नोटिस।

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1989

का.आ. 684(अ):—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के अम
मंत्रालय को अधिसूचना सं. का.आ. 527(अ) और का.आ. 628(अ),
जो दोनों तारीखें 17 जुलाई, 1988 को हैं, अम जीवी पत्रकार और
अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों को शर्तें और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम,
1955 (1955 का 45) की धारा 9 और धारा 13 के अधीन अम जीवी
पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारियों को सज्जदो-दरे निर्धारित
या पुनरीक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक सेवा
निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री यू. एस. बठाला की अध्यक्षता में दो
सदस्यों के बोर्ड का गठन किया गया।

और उक्त बोर्डों ने अपनी सिफारिशें कर दी हैं:

और केन्द्रीय सरकार उक्त सिफारिशों में कुछ उपांतर करते का
प्रस्ताव करती है जो उसके विचार में उक्त सिफारिशों के स्वरूप में महत्व-
पूर्ण परिवर्तन करते हैं:—

अब, प्रतः, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के
खण्ड (क) के परन्तुक के अनुसरण में ऐसे सभी व्यक्तियों को जिनके
निम्नलिखित उपांतरणों द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, सूचना दी
जाती है कि वे उस तारीख से जिसको राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना
की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि
के भीतर लिखित रूप में निम्नलिखित को अभ्यावेदन भेजे:—

सचिव,
भारत सरकार,
अम मंत्रालय,
अम शक्ति भवन,
नई दिल्ली।
प्रस्तावित उपांतरण :

(i) अम जीवी पत्रकार और गैर अम जीवी पत्रकार
कर्मचारियों के लिए बोर्डों की सिफारिशों के अध्याय 9 के अधीन भाग

1 के अनुभाग 5 के अधीन मकान किराया भत्ता के संबंध में, सारणी
3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

सारणी-3

(मकान किराया भत्ता की दर (घेतन का प्रतिशत)

समाचारपत्र स्था- 20 लाख और 10 से 20 लाख 10 लाख से कम
पत्र की वर्ग उससे अधिक की के बीच की जनसंख्या की जनसंख्या वाले
जनसंख्या वाले वाले नगर/कस्बे नगर/कस्बे
नगर, कस्बे

1	2	3	4
IV	15	14	13
V	14	13	12
VI	13	12	11
VII	12	11	10
VIII	11	10	9
IX	10	9	8
X	9	8	7
XI	8	7	6
XII	7	6	5
XIII	6	5	4

टिप्पणी:— ऊपर वर्णित मकान किराया भत्ते की दर, किसी भी नगर
में समाचारपत्र स्थापन के किसी वर्ग के अधीन कर्मचारियों
के किसी समूह के लिए 1200 रुपये के अधिकतम के
अधीन रहते हुए होगी।

(ii) अध्याय 9 के अधीन भाग 1 के अनुभाग 5 के अधीन नगर
प्रतिभारदात्मक भत्ता के संबंध में सारणी IV के स्थान पर निम्नलिखित
सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

न. रणी-4

नगरप्रतिभारदात्मक भत्ता

(दर प्रतिमास)

स्थापन का वर्ग	20 लाख या उससे अधिक संख्या वाले नगर/कस्बे	10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	4 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर/कस्बे
1	2	3	4
IV	100	75	20
V	75	50	20
VI	60	35	20
VII	50	30	20

1	2	3	4
IV	45	30	20
V	40	30	20
VI	40	30	20
VII	40	30	20
VIII	50	30	20
IX	40	30	20

1 जनवरी, 1988 से आगे की अवधि के लिए पहले से दिया गया
मकान किराया भत्ता प्रस्तावित उपतिरणों के अधीन जब वे अंतिम
रूप से अधिवृद्धित कर दिए जाएं, अनुसूचित मकान किराया भत्ता के मुद्दे
समायोजित किया जाएगा।

[सं. एस. 33014/1/89-इस्यू. बी.]

MINISTRY OF LABOUR

NOTICE UNDER WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCE- LLANEOUS PROVISIONS ACT, 1955 TO NEWSPAPER ESTABLISHMENT EMPLO- YEEES AND THEIR WORKING JOURNALISTS AND NON-JOURNALIST EMPLOYEES.

New Delhi, the 31st August, 1989

S.O. 684 (E):—Whereas the Central Govern-
ment by the notifications of the Government
of India in the Ministry of Labour Nos. S.O.
527(E) and S. O. 528(E), both dated the 17th
July, 1985 constituted two wage boards under
section 9 and section 13C of the Working Jour-
nalists and other Newspaper Employees (Condi-
tions of Service) and Miscellaneous Provisions
Act, 1955 (45 of 1955) under the Chairmanship
of Justice Shri U. N. Bhachawat, a retired Judge
of the Madhya Pradesh High Court for fixing
or revising the rates of wages of working journa-
lists and non-journalist newspaper employees;

And whereas, the said Boards have made their
recommendations;

And whereas, the Central Government pro-
poses to make certain modifications to the said
recommendations, which in its opinion affect
important alterations in the character of the
said recommendations;

Now therefore, in pursuance of the proviso
to clause (a) of sub-section (2) of section 12 of
the said Act notice is hereby given to all persons

likely to be affected by the following modifications to make their representations in writing within a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public to :

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour,
Shram Shakti Bhavan,
New Delhi.

Proposed modifications :

- (i) For Table III, in relation to the House Rent Allowance under section V of Part I under Chapter IX of the recommendations of the Boards for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees, the following Table shall be substituted namely :—

TABLE III

Rates of House Rent Allowance
(Percentage of Pay)

Class of Newspaper Establishment.	Cities/Towns with population of 20 lakhs and above.	Cities/Towns with population between 10 to 20 lakhs	Cities/Towns with population less than 10 lakhs.
IA	15	14	13
I	14	13	12
II	13	12	11
III	12	11	10
IV	11	10	9
V	10	9	8
VI	9	8	7
VII	8	7	6
VIII	7	6	5
IX	6	5	4

Note :— The rates of House Rent Allowance mentioned above are subject to a maximum of Rs. 1200/- for any group of employees under any class of newspaper establishment in any city.

- (ii) For Table IV in relation to City Compensatory Allowance under Section V of Part I under Chapter IX, the following table shall be substituted, namely :—

TABLE IV
CITY COMPENSATORY ALLOWANCE
(Rates per mensem)

Class of Establishment	Cities/Towns with population of 20 lakhs and above.	Cities/Towns with population between 10 to 20 lakhs.	Cities/Towns with population of 4 lakhs or more.
	Rs.	Rs.	Rs.
IA	100	75	20
I	75	50	20
II	60	35	20
III	50	30	20
IV	45	30	20
V	40	30	20
VI	40	30	20
VII	40	30	20
VIII	40	30	20
IX	40	30	20

The House Rent Allowance already paid for the period commencing on the 1st day of January, 1988 onwards shall be adjusted against the House Rent Allowance admissible under the proposed modifications as and when finally notified

[No. S—33014/1/89-W.B.]

श्रम जीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 के अर्धीन समाचार-पत्रों की नियोजकों और उनके श्रम जीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों को नोटिस।

का.आ. 685(अ) :—केंद्रीय सरकार व भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिनियम सं. का.आ. 527(अ) और का.आ. 528 (अ), जो दोनों तारीख 17 जुलाई, 1985 की है, श्रम जीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1985 का. 45) की धारा 9 और धारा 13ग के अधीन श्रम जीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार पत्रों के कर्मचारियों की मजदूरी-दरों निर्धारित या पुनर्निर्धारित करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री यू. एन. बछावत की अध्यक्षता में दो मजदूरी बोर्डों का गठन किया था।

और उक्त बोर्डों ने अपनी सिफारिशें कर दी हैं;

और केंद्रीय सरकार उक्त सिफारिशों में कुछ उपकरण करने का प्रस्ताव करती है जो उसके विचार में उक्त सिफारिशों के स्वभाव में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं :—

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) के परन्तुक के अनुसरण में ऐसे सभी व्यक्तियों को जिनके निम्नलिखित उपांतरणों द्वारा प्रभावित होने की संभावना है सूचना दी जाती है कि वे उस तारीख से जिसको राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की

प्रतियां जलता की उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में निम्नलिखित को सम्पादक भेजे:—

सचिव,
भारत सरकार,
श्रम मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली।
प्रस्तावित उपांतरण :

(i) श्रम जीवी पत्रकार और गैर-श्रम जीवी समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए बोर्डों की सिफारिशों के अध्याय 9 के अधीन भाग II के अनुभाग 5 के अधीन मकान किराया भत्ता के संबंध में, सारणी 3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

सारणी-3

(मकान किराया भत्ता की दरबन्धन का प्रतिफल)

समाचार एजेंसी का वर्ग	20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 से 20 लाख की बीच की जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 लाख से कम की जनसंख्या वाले नगर/कस्बे
I	15	14	13
II	16	14	13

टिप्पण:— ऊपर वर्णित मकान किराया भत्ते की दर किसी भी नगर में समाचारपत्र एजेंसी के किसी वर्ग के अधीन कर्मचारियों के किसी समूह के लिए 1200 रुपये के अधिकतम के अधीन रहते हुए होगी।

(ii) अध्याय 9 के अधीन भाग II के अनुभाग 5 के अधीन नगर प्रतिकरात्मक भत्ता के संबंध में सारणी IV के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

सारणी-4

नगर प्रतिकरात्मक भत्ता

(दर प्रतिमास)

स्थान का वर्ग	20 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 से 20 लाख की बीच जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	4 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर/कस्बे
	रु.	रु.	रु.
I	100	75	20
II	75	50	20

1 जनवरी, 1988 से भागों की अवधि के लिए पहले से दिया गया मकान किराया भत्ता प्रस्तावित उपांतरणों के अधीन जब के अंतिम

रूप से अधिसूचित कर दिए जाएंगे, अनुशेष मकान किराया भत्ता के मद्दे सम्पादित किया जाएगा।

[सं. एम.-33014/1/89-इक्यू.जी.]

पदमा चैकटाचलम, उप सचिव

NOTICE UNDER WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1955 TO NEWS AGENCY EMPLOYERS AND THEIR WORKING JOURNALISTS AND NON-JOURNALIST EMPLOYEES.

S.O. 685 (E):—Whereas the Central Government by the notifications of the Government of India in the Ministry of Labour Nos. S. O. 527 (E) and S.O. 528(E) both dated the 17th July, 1985 constituted two wage boards under section 9 and section 13C of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) under the Chairmanship of Justice Shri U. N. Bhachawat, a retired Judge of the Madhya Pradesh High Court for fixing or revising the rates of wages of working journalists and non-journalist news agency employees;

And whereas, the said Boards have made their recommendations;

And whereas, the Central Government proposes to make certain modifications to the said recommendations, which is its opinion affect important alterations in the character of the said recommendations;

Now therefore, in pursuance of the proviso to clause (A) of sub-section (2) of section 12 of the said Act notice is hereby given to all persons likely to be affected by the following modifications to make their representations in writing within a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public to:

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour,
Shram Shakti Bhavan,
New Delhi.

Proposed modifications :

- (i) For Table III, in relation to the House Rent Allowance under Section V of Part II under Chapter IX of the recommendations of the Boards for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees, the following Table shall be substituted namely :—

TABLE III
Rates of House Rent Allowance
(Percentage of Pay)

Class of News Agency	Cities/Towns with population of 20 lakhs and above	Cities/Towns with population between 10 to 20 lakhs	Cities/Towns with population of less than 10 lakhs.
I	15	14	13
II	15	14	13

Note :— The rates of House Rent Allowance mentioned above are subject to a maximum of Rs. 1200/- for any group of employees under any class of News Agency in any city.

- (ii) For Table IV in relation to City Compensatory Allowance under Section V of Part II under Chapter IX, the following table shall be substituted, namely:—

TABLE IV
Rates of City Compensatory Allowance
(Rates per mensem)

Class of Establishment	Cities/Towns with population of 20 lakhs and above	Cities/Towns with population between 10 to 20 lakhs	Cities/Towns with population of 4 lakhs or more.
	Rs.	Rs.	Rs.
I	100	75	20
II	75	50	20

The House Rent Allowance already paid for the period commencing on the 1st day of January, 1988 onwards shall be adjusted against the House Rent Allowance admissible under the proposed modifications as and when finally notified.

[No. S—33014/1/89-WB.]

PADMA VENKATACHALAM, Dy. Secy.

